वर्ष 2 अंक 10 अक्टूबर 1980 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

"अधिनायकवाद के खिलाफ एक व्यापक मोर्चे के लिए!"

—बी. टी. रणदिवे

[कन्नानोर में 11-14 सितंबर को हुई सीटू जनरल काउंसिल की बैठक में सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण के कुछ अंश हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं.]

सीटू के चौथे सम्मेलन तथा वर्तमान बैठक के बीच के समय में गुजरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीटू अध्यक्ष रणदिवे ने जनरल काउंसिल का ध्यान विश्व स्तर पर उभर रहे युद्ध के खतरे की ओर दिलाया. इस खतरे से शांति व जनतंत्र प्रेमी विश्व की तमाम जनता चिंतित है. अमरीका द्वारा दुनिया में यह अफवाह फैलाने कि रूस से अमरीका सहित सभी देशों को खतरा है के बारे में रणदिवे ने कहा. "इस प्रकार की अफवाहें फैलाने के पीछे अमरीका का असली उद्देश्य अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा करना व सभी देशों पर प्रभुत्व स्थापित करना है. समाजवादी देशों के लिए अमरीका के ये इरादे और अधिक खतरनाक हैं."

शांति को खतरा

सीटू अध्यक्ष रणदिवे ने भारत के मजदूर वर्ग को आह्वान किया कि विश्व शांति को तोड़ने, समाजवादी देशों को धमकी देने तथा तीसरी दुनिया के देशों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करने के साम्राज्यवादी मंसूबों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं. अंतर्राष्ट्रीयवाद के झंडे को बुलंद करते हुए मजदूर वर्ग को शांति व समाजवाद पर मंडराते खतरों के प्रति सचेत रहना चाहिए.

नई योजना का ढांचा

प्रस्तावित नई योजना के ढांचे के बारे में चर्चा करते हुए रणदिवे ने बताया कि कांग्रेस (आई) में पुरानी योजनाओं व नीतियों की असफलताओं से कोई सबक हासिल नहीं किया हैं. वे पुरानी नीतियों के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तथा तीव्र विकास व गरीबी दूर करने के उपाय करने के बजाय केवल अंकों की जादूगरी दिखाने में व्यस्त हैं. रणदिवे ने साफ कहा : "योजना के प्रस्तावित ढांचे में एकाधिकारी घरानों या बड़ी पूंजी की गिरफ्त को कम करने के बारे में कोई सुझाव नहीं हैं. सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाने के बारे में भी केवल दिखावटी सहानुभूति दर्शाई गई है." जबकि यह सरकार बार-बार कहती है कि बुनियादी अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण निर्देशित सिद्धांत हैं किंतु इस दिशा में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही. उदाहरण के लिए सम्पत्ति के जमाव को कम करना एक निर्देशित सिद्धांत है. सरकार को इस सिद्धांत को असली जामा पहुंचाने से कौन रोकता है ? सरकार एकाधिकारी घरानों व बड़ी पूंजी के जमाव को क्यों नहीं खत्म करती ?

निजी क्षेत्र की चर्चा करते हुए रणदिवे ने कहा : "इस बारे में कोई प्रमाण नहीं मिलता कि निजी क्षेत्र पर कोई अंकुश लगाया जाएगा या देश की अर्थव्यवस्था में उसके प्रभुत्व को धीरे-धीरे कम किया जाएगा. योजनाशास्त्रियों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा देश की अर्थव्यवस्था में उनकी घुसपैठ, दवा उद्योग में सभी कानून तोड़कर एकाधिपत्य जमाने के उनके प्रयत्नों व मजदूरों के खिलाफ उनके हमलों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है. किंतु इस सबमें कोई आश्चर्य भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस (आई) का चुनाव घोषणापत्र भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिलकुल चुप है."

भूमि संबंध

भूमि संबंधों में बुनियादी परिवर्तन लाए बिना तथा भूमि के जमाव को खत्म कर गरीब किसानों व खेतिहर मजदूरों में जमीन को बांटे बिना औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार नहीं किया जा सकता. इस योजना के बनाने वाले इस दिशा में

प्रगति न होने के कारणों में राजनीतिक उत्साह की कमी के बारे में बात करते हैं. किंतु वे यह नहीं बताते कि इसके लिए दोषी शासक कांग्रेस पार्टी है जिसने इस बारे में कभी कोई पहल नहीं दिखाई है. इस संदर्भ में बी. टी. ग्रार. ने कहा : "केरल सरकार द्वारा पास किए गए प्रगतिशील भूमि सुधार बिल को अब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल पाई है. पिछले तीस सालों से भूमि की उच्चतम सीमा तय करने व फालतू जमीन भूमिहीनों में बांटने के हर प्रयत्न मजाकिया नाटकों की भांति हंसी-मजाक में समाप्त हो गए हैं और इन्हें कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया. इसका कारण है कि शासक पार्टी पर जमींदारों व ग्रामीण क्षेत्रों के निहित स्वार्थों का प्रभुत्व है और इस कारण किसी प्रगतिशील कदम को अमल में लाने के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का इसमें अभाव है." इसका नतीजा यह है कि भूमि का जमाव बरकरार है. बी. टी. ग्रार. ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा भेजी गई उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें बताया गया है कि आजादी के तीस वर्ष बाद भी 40 करोड़ अतिरिक्त भूमि में से केवल 40 लाख एकड़ भूमि ही भूमिहीन किसानों व खेतिहर मजदूरों में बांटे जाने के लिए तैयार हो पाई है.

नया भार

नई योजना के मसौदे में राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो सुझाव दिये गए हैं, उनसे यह साफ लगता है कि इस सबका बोझ आम जनता पर पड़ेगा व इससे उनके आर्थिक हालात और बदतर हो जाएंगे. नई योजना में 19 हजार करोड़ रुपये के बराबर साधन-संग्रहण (रिसोर्स मोबिलाइजेशन) तथा 17,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों का भार अप्रत्यक्ष करों द्वारा आम आदमी के ऊपर ही पड़ना है. इसके परिणामस्वरूप आबकारी, बिक्री कर आदि के द्वारा जीवनयापन की आम चीजों के मूल्यों में वृद्धि होगी. झा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल करों के भुगतान का 80 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से ही प्राप्त होता है. छठी योजना की अवधि में यह और अधिक बढ़ जाएगा.

सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को हल्का करने के लिए तथा विनियोग के लिए धन एकत्र करने के लिए खाद, भोजन, निर्यात आदि को दी जाने वाली सहायता को वापिस ले लेने का सुझाव योजना के मसौदे में दिया गया है. रणदिवे ने बताया कि इस प्रकार का प्रस्ताव विश्व बैंक के दबाव के कारण पेश किया जा रहा है. अपनी हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में बैंक ने इस प्रकार की सहायता को समाप्त करने का निर्देश दिया है और हमारे वित्त मंत्री ने तत्काल इसे मान लिया. खाद में दी जाने वाली सहायता वापिस लिये जाने से उन लाखों मझोले किसानों को नुकसान पहुंचेगा जो पहले ही महंगाई व अपने उत्पादन का सही दाम न मिलने से परेशान हैं. खाद्यान में दी जाने वाली सहायता वापस ले लेने से खाद्यान की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी जिसका सामना मजदूरों व आम शहरवासियों को करना पड़ेगा. हमारे योजनाशास्त्रियों का महंगाई को रोकने का यह अभूतपूर्व तरीका है.

निर्यात में दी जाने वाली सहायता को समाप्त करने के प्रस्ताव का भी भारतीय जनता ने विरोध किया है. इसका एक बुरा असर तो यह होगा कि निर्यात से होने वाला लाभ कुछ एक बड़े पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगा. अमरीका साम्राज्यवादी भी इस प्रकार के प्रस्ताव की राजनीतिक भेदभाव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं अमरीकी सरकार ने हाल में ही भारतीय सामान पर 40 करोड़ रुपये का शुल्क लगा दिया है. विदेशी सहायता के सवाल पर भी इसी प्रकार के दबाव सामने आ रहे हैं. बी. टी. ग्रार. ने जनरल काउंसिल को बताया कि भारतीय जनता पर कर्जों की अदायगी की सख्त शर्तें लादी जा रही हैं. योजनाशास्त्री व्यावसायिक शर्तों व ब्याज के ऊंचे दरों पर ऋण लेने की योजनाएं बना रहे हैं. बी.टी.ग्रार. ने चेतावनी दी कि व्यावसायिक शर्तों व ओपेक ऋणों का भारी दबाव भारतीय जनता पर पड़ने जा रहा है.

मूल्य-वृद्धि बरकरार

सीटू अध्यक्ष ने बताया कि कीमतें कम होने के कोई आसार नजर नहीं आते. सरकार भी कीमतें कम करने के बारे में कुछ नहीं कहती. वह केवल कीमतों को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखने का आश्वासन देती है. किंतु इन आश्वासनों के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं. किसानों को दिया गया यह आश्वासन कि उनके उत्पादन की सही कीमत दी जाएगी को भी पूरा नहीं किया जा रहा है.

योजना व मजदूर वर्ग

किसी भी प्रकार की योजना की सफलता के लिए मजदूरों की सहायता व भागेदारी आवश्यक है. किंतु कांग्रेस (आई) के घोषणापत्र के समान ही हमारे योजना शास्त्रियों के पास भी इस संबंध में करने को कुछ नहीं है. हमारे योजना शास्त्री जो एकाधिकारी घरानों को छूट पर छूट देने को तैयार हैं मजदूर वर्ग के प्रति उदारता का मुखौटा पहनना भी आवश्यक नहीं समझते. बी. टी. आर. ने कहा : "वे कहते हैं कि मजदूर वर्ग की कोई समस्याएं नहीं हैं, कोई मांगें नहीं हैं, कोई शिकायतें नहीं हैं. योजना के ढांचे में वे हर श्रेणी को राहत देने को तैयार हैं पर मजदूर वर्ग को नहीं". योजना के निर्माता मैनेजमैंट की ऊंची श्रेणियों की मोटी तनख्वाहों में और अधिक वृद्धि करने को तत्पर हैं किंतु मजदूरों के लिए इस प्रकार के प्रोत्साहन या लाभ देने की वे कोई जरूरत नहीं समझते. उनके दिमाग में केवल एक ही बात है और वह है कि मजदूर वर्ग द्वारा अपने जीवनयापन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए छेड़े गए संघर्षों को किस प्रकार दबाया जाए. कानूनों व अध्यादेशों द्वारा वे संघर्षों पर पाबंदी लगाते रहते हैं.

प्रबंध में मजदूरों की भागेदारी के सवाल पर रणदिवे ने बताया कि हालांकि योजनाशास्त्रियों ने इस प्रकार के सुझाव दिए हैं पर इस बारे में वे गंभीर नहीं हैं. मजदूरों की प्रबंध में

भागेदारी के पीछे उनकी मंशा केवल उत्पादन को बढ़ाने तक ही सीमित है. दूसरे शब्दों में इसका मतलब है—काम के घंटों को बढ़ाना व अधिक शोषण. सीटू या ट्रेड यूनियन आंदोलन जब उत्पादन प्रक्रिया में मजदूरों की भागेदारी की बात करता है तो उसका अर्थ है हर स्तर पर बराबरी के आधार पर भागेदारी जिससे कि उद्योग में कार्यकुशलता बढ़ने के साथ-साथ भ्रष्टाचार व अनियमितताएं खत्म हों. किंतु योजना के निर्माताओं का भागेदारी से कुछ और ही तात्पर्य है. योजना का प्रारूप साफ तरह से मजदूर विरोधी है. मजदूर वर्ग को इस प्रकार के दृष्टिकोण से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा.

बेरोजगारी

अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत की एक झलक बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़ों से भी मिल जाती है. पिछले दस वर्षों में बेरोजगारी तीन गुना बढ़ गई है. रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 1970 में 40.7 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे. 1978 में इनकी संख्या 126.2 लाख और जनवरी 1980 में 144.4 लाख हो गई. 1979 के पंजीकृत बेरोजगारों में लगभग 40 लाख मैट्रिक थे तथा 14 लाख बी. ए. व एम. ए. पास थे.

ट्रेड यूनियन आंदोलन की हमेशा यह मांग रही है कि रोजगार के अधिकार को बुनियादी अधिकार मान लिया जाए और जब तक सभी को रोजगार देना संभव न हो तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए. किंतु कांग्रेस (आई) सरकारों ने अब तक यह मांग स्वीकार नहीं की है. हाल ही में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त लोगों से लड़वाने के प्रयत्न भी हुए हैं. पिछले वर्ष जब अहमदाबाद के बैंक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे तब उन पर भाड़े के व्यक्तियों द्वारा हमले करवाए गए. ये भाड़े के गुंडे अपने आपको बेरोजगार बताते थे. स्मरणीय है कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बेरोजगारी भत्ता मिलने की मांग का यह कहकर मजाक उड़ाया कि यह तो भीख मांगने के समान है. बी. टी. रणदिवे ने बताया: "ट्रेड यूनियन आंदोलन बेरोजगारी की समस्या से आंख नहीं मूंद सकता. समय आ गया है कि हम अन्य केंद्रीय संगठनों के साथ एकजुट होकर बेरोजगारी की समस्या को रेखांकित करें तथा बेरोजगारों का एक देशव्यापी सम्मेलन आयोजित कर सारे देश में एक ही प्रकार के बेरोजगारी भत्ता मिलने की मांग को उठाएं."

रणदिवे ने इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल व केरल की सरकारों की सराहना की जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते की योजना को लागू किया है. इन दोनों राज्यों में बूढ़ी विधवाओं के लिए भी पेंशन की योजना लागू की गई है. इसका असर अन्य राज्यों पर भी हुआ है और अब कई राज्यों में कमोबेश रूप में कुछ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. सीटू अध्यक्ष ने बताया कि इन कदमों से बेरोजगारों के लिए ट्रेड यूनियनों के संघर्ष में काफी सहायता मिली है. उन्होंने आह्वान किया कि हमारी सारी शक्ति पूरे देश के लिए बेरोजगारी भत्ते की एक समान योजना के लागू करवाने पर लगनी चाहिए.

औद्योगिक संबंध बिल

केंद्रीय सरकार द्वारा बदनाम औद्योगिक संबंध बिल में कुछ फेरबदल कर इसे दुबारा लागू करने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए रणदिवे ने बताया: "वे लोग जो औद्योगिक अशांति को कम करना व उत्पादन की हानि को रोकना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे समस्याओं को देखने का अपना पुराना दृष्टिकोण छोड़ दें. यह दकियानूसी दृष्टिकोण है जो मजदूर वर्ग को उद्योग-क्षेत्र में घुसा हुआ एक अवांछनीय तत्व मानता है व बेहतर जीवन व्यतीत करने के प्रयोजन के लिए उनके द्वारा रखी जा रही मांगों को गलत बताता है. इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने का स्वाभाविक परिणाम है मजदूर वर्ग पर दमन." उन्होंने कहा: "हमारे शासक लोग यह नहीं सोचते कि प्रजातंत्र की आवश्यकता न केवल सरकार चलाने के लिए होती है बल्कि उद्योग चलाने के लिए भी होती है."

सीटू अध्यक्ष ने बताया: "औद्योगिक अशांति व उत्पादन के नुकसान को कम करने के लिए चार बातें जरूरी हैं. पहली यह है कि उद्योग में संतोषजनक वेतन समझौता हो. दूसरे, समझौता बातचीत करने वाली यूनियन मजदूरों का सही प्रतिनिधित्व करती हो. इसका यह अर्थ हुआ कि यूनियन की मान्यता का फैसला गुप्त मतदान के आधार पर हो. तीसरे, सभी समझौतों को मजदूरों का आम समर्थन प्राप्त हो. चौथे, मजदूरों को बराबरी के आधार पर उद्योग में भागेदारी का अधिकार मिले. यदि मजदूरों को सच्चे अर्थों में भागेदारी का अधिकार मिले तो इससे अशांति व उत्पादन में गिरावट के बहुत से कारण तो स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे."

किंतु सभी औद्योगिक संबंध कानूनों का मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्ग द्वारा अपने जीवन स्तर की बेहतरी के लिए किए जाने वाले संघर्षों पर पाबंदी लगाना है. कुछ नये परिवर्तन करके इस बिल के दायरे को और बढ़ाने के सुझाव हैं. एक प्रस्तावित सुझाव के अनुसार हस्पतालों तथा शैक्षणिक व शोध संस्थानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा. ठीक इसी प्रकार का एक कदम जनता सरकार ने उठाया था. प्रस्तावित सुझावों का भी ऐसा ही उद्देश्य है. रणदिवे ने बताया: "मेहनतकश जनता के हर वर्ग के लिए एक ही कानून होना चाहिए और इस कानून में अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए."

सीटू अध्यक्ष ने उस सुझाव की चर्चा की जिसके अनुसार दो यूनियनों या यूनियन व सरकार के बीच उत्पन्न हुए विवादों को एक श्रम अदालत में पेश किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा. उन्होंने बताया कि यह यूनियनों के आपसी विवादों को सुलझाने की आड़ में चापलूसी-पसंद यूनियनों को मदद करने का एक तरीका है और इससे जुझारू ट्रेड यूनियन आंदोलन को नुकसान होगा.

औद्योगिक तनाव को दूर करने के लिए मालिकों द्वारा मजदूरों को मनमाने ढंग से नौकरी से निकालने व तंग करने के अधिकारों पर अंकुश लगाना होगा. ये मनमाने अधिकार मज-

दूरों के विक्टिमाइजेशन का कारण बनते हैं. बी. टी. आर. ने विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हुए संघर्षों व इससे हुए उत्पादन-दिनों के नुकसान के आंकड़े दिए.

श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

जुलाई में दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन जिसमें ट्रेड यूनियन विषयों पर बहस हुई का हवाला देते हुए सीटू अध्यक्ष ने बताया कि इस सम्मेलन में फैसला किया गया कि ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम सदस्य संख्या को बढ़ाया जाएगा. कई राज्यों में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार का दफ्तर पुलिस विभाग के एक अंग के रूप में काम कर रहा है. ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या के बढ़ाए जाने वाला संशोधन पंजीकरण की प्रक्रिया में झूठ व धोखाधड़ी को बढ़ावा देगा और इससे केवल शासक पार्टी को ही फायदा होगा.

सीटू अध्यक्ष ने सम्मेलन में गुप्त मतदान के आधार पर मजदूरों के प्रतिनिधियों को चुने जाने के मुद्दे पर हुई आम सहमति का स्वागत किया. उन्होंने एक्ट में कुछ परिवर्तन कर ग्रामीण व खेतिहर मजदूरों की यूनियनों को भी इसमें शामिल करने के सुझाव का समर्थन किया. उन्होंने आगे कहा : "हमें यूनियनों की कार्यकारिणी में फैक्ट्री से बाहर के अनुभवी ट्रेड यूनियन नेताओं को शामिल किये जाने पर लगी सीमा का विरोध करना होगा. इस प्रकार के अनुभवी व कारगर मजदूर नेताओं को 'बाहरी तत्व' मानना गलत होगा. सरकार की ओर से इस प्रकार के व्यक्तियों से संबद्ध होने से रोकने या उनकी संख्या को सीमित किया जाने का असली प्रयोजन मजदूरों को डराना, धमकाना व उनको ऐसे अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से वंचित रखना है. उससे ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर होगा."

ई. एस. आई. तथा ई. पी. एफ. में मालिकों द्वारा राशि जमा न कराने के मुद्दे पर बोलते हुए बी. टी. आर. ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष रिकवरी सैल बनाने का सुझाव देने के अलावा सम्मेलन ने और कोई ठोस बात नहीं कही. वे इस प्रकार के मालिकों को कोई सजा देने की सिफारिश भी न कर सके. रणदिवे ने कहा कि जब इस प्रकार के मालिकों में कई केंद्रीय व राज्य सरकारों के संस्थान भी हैं तो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन चुप्पी साधने के अलावा और कर भी क्या सकता है. महिलाओं के लिए रोजगार-प्रशिक्षण के सुझाव के बारे में उन्होंने कहा कि अब देखना है कि इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे.

वामपंथी मोर्चा सरकारें

कांग्रेस (आई) शासित प्रदेशों में मजदूर वर्ग के खिलाफ प्रयोग की जा रही दमन की मशीनरी की निंदा करते हुए रणदिवे ने बताया कि पश्चिम बंगाल व केरल की सरकारों के पास वैकल्पिक नीतियां मौजूद हैं. मजदूरों के अधिकारों को कम करने या उनका दमन करने के बजाय ये सरकारें उन्हें मजबूत करती हैं और आगे बढ़ाती हैं. वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे शोषकों के खिलाफ शोषितों के अधिकारों की रक्षा करना चाहती हैं. पश्चिम बंगाल की सरकार हड़ताल पर जाने, संगठित होने व सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है. उसने राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा मजदूरों के हर वर्ग को हर प्रकार की सुविधाएं दी हैं. वामपंथी मोर्चा सरकारों की भूमिका की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया : "वे एक ऐसे प्रशासन को जनवादी आधार प्रदान कर रहे हैं जो अपने जन-विरोधी रुझानों के लिए हमेशा बदनाम रहा है. इस कारण ये तीन सरकारें अधिकनायकवाद के बढ़ते हुए खतरे के बीच जन-वाद का आधार स्तम्भ हैं. सीटू तथा भारत के मजदूर वर्ग का यह दायित्व हो जाता है कि वह इन स्तंभों की रक्षा करें हम सीटू के उपाध्यक्ष ज्योति बसु तथा दोस्तों ई. के. नयनार व नृपेण चक्रवर्ती को अभिवादन भेजते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी शक्ति से उनके साथ हैं."

सीटू के नेतृत्व में वर्किंग वीमैंज कोआर्डिनेशन कमेटी के काम का जिक्र करते हुए रणदिवे ने बताया कि औरतों के अधिकारों की रक्षा, ट्रेड यूनियन आंदोलन में उनकी भूमिका, ट्रेड यूनियनों में उनकी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति तथा अन्य संबंधित कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे आंदोलन से संबंधित हैं और इन्हें तेजी से हल किया जाना चाहिए.

सीटू अध्यक्ष ने असम में सीटू कार्यकर्ताओं व राज्य सीटू कार्यालय पर हो रहे हमलों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हत्याओं व हमलों के बावजूद हमारे साथी मजदूर वर्ग का परचम झुकाने को तैयार नहीं हैं व मजदूर वर्ग व देश की एकता की रक्षा के लिए तत्पर हैं. उन्होंने इस प्रकार शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि दी.

त्रिपुरा के विपदाग्रस्त लोगों की सहायता के लिए ट्रेड यूनियनों द्वारा धन एकत्र करने का जिक्र करते हुए रणदिवे ने बताया कि त्रिपुरा की दुःखद घटनाएं राष्ट्र-विरोधी तत्वों के षड्यंत्रों का परिणाम थी जो उत्तर-पूर्व के अन्य कुछ राज्यों की भांति इस राज्य में भी अशांति फैलाना चाहते थे. किंतु उनके प्रयास आमतौर पर असफल रहे. त्रिपुरा की जनजातियों व बंगालियों को एकजुट करता हुआ जनवादी आंदोलन सी. पी. आइ. (एम.) के नेतृत्व में मजबूत हो गया था. इसकी मजबूती का एक प्रमाण संसद तथा राज्य एसेम्बली दोनों के चुनावों में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व में वामपंथी मोर्चे की भारी जीत है. त्रिपुरा की इस एकता को तोड़ने के लिए षड्यंत्र-कारियों ने आम आदमियों पर हमले करने व उन्हें जान से मार देने का सिलसिला आरम्भ कर दिया. बी. टी. रणदिवे ने कहा: "एक ओर आमरा बंगाली संस्था ने तथा दूसरी ओर जनजातियों के बीच घुसे कुछ वाम दुस्साहसवादी तत्वों ने जातिवादी भावनाएं भड़काकर एक दूसरे को मदद पहुंचाने की कोशिश की. इसका लाभ राष्ट्रविरोधी तत्वों ने तुरंत ले लिया. हालात का फायदा उठाते हुए कांग्रेस (आई) के कुछ तत्वों ने त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

कन्नानोर में जनरल काउंसिल की बैठक : एक समीक्षा

10 सितंबर : जयंती जनता एक्सप्रेस तेजी से कनानोर की ओर दौड़ी जा रही है. मंजिल आने में केवल एक घंटा बाकी है. रेल पटरियों के दोनों ओर हम मकानों की छतों पर सीटू के लाल झंडे लहराते देख रहे हैं. मंजिल नजदीक आने के साथ-साथ झंडों तथा सजावट की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है. आखिर कनानोर स्टेशन आ ही गया. लाल झंडों से सजा स्टेशन सीटू जिंदाबाद, सीटू लाल सलाम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है. स्वागत समिति के अध्यक्ष सी. कन्नन के नेतृत्व में वालंटियर जनरल काउंसिल के सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं.

जनरल काउंसिल की बैठक सी. पी. आई. (एम) के कन्नानोर जिला समिति के प्रांगण में स्थित ए. के. जी. मेमोरियल हाल में होने जा रही है. सीटू का केंद्रीय कार्यालय काम करना शुरू कर देता है. वालंटियर विभिन्न प्रकार के काम करने में व्यस्त हैं. गतिविधियां पूरे जोर से चल रही हैं. देश के हर कोने से जनरल काउंसिल के सदस्यों के आगमन के समाचार मिल रहे हैं.

11 सितंबर : जनरल काउंसिल के सदस्य केंद्रीय कार्यालय में आ रहे हैं. वे कई विषयों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. उद्योग-स्तर की बैठकें हो रही हैं. उद्योगों के स्तर पर देशव्यापी संघर्ष छेड़ने के कार्यक्रम बन रहे हैं.

सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक अपराह्न 3.30 पर होती है. इसमें शहीदों पर श्रद्धांजलि के प्रस्ताव पास होते हैं. इसमें जनरल काउंसिल की बैठक का कार्यक्रम भी तय होता है.

चार बजे हाल खचाखच भरा है. जनरल काउंसिल के सदस्य व अन्य लोग उपस्थित हैं. सदस्य मजदूर वर्ग तथा आम जनता के फौरी मुद्दों पर संघर्ष चलाने के लिए आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करते हैं.

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति माइक पर आते हैं. वे सूचना देते हैं कि हमारे अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे अस्वस्थ हैं. डाक्टरों ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे बिस्तर पर आराम करें व बैठक में भाग न लें. इस कारण पी. राममूर्ति अध्यक्ष पद के लिए मुहम्मद इस्माइल के नाम को प्रस्तावित करते हैं.

सीटू उपाध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल बैठक को विधिवत आरंभ करते हैं. सभी साथी सभाभवन से बाहर आते हैं. तालियों की गड़गड़ाहट व नारों की गूंज के बीच मुहम्मद इस्माइल सीटू का झंडा फहराते हैं. इसके बाद सभी साथी हाल में स्थान ग्रहण कर लेते हैं. सीटू के उपाध्यक्ष व स्वागत-समिति के अध्यक्ष सी. कन्नन बैठक का अभिवादन करते हैं. सदस्यों का स्वागत करते हुए वे संक्षेप में कन्नानोर जिले में ट्रेडयूनियन आंदोलन के विकास तथा मजदूरों तथा आम जनता पर हुए दमन का ब्यौरा देते हैं.

सीटू सचिव एम. के. पंधे शहीदों के सम्मान में प्रस्ताव पास करते हैं. इन शहीदों में टान इक थांग, मार्शल टीटो, सुहृद मल्लिक चौधरी, दीनेन भट्टाचार्य, तरूण सेनगुप्त, बी.के. पालीवाल, के. पद्मनाभन तथा टी. बालन शामिल हैं. सभी उपस्थित साथी इनके सम्मान में खड़े होते हैं व श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे का भाषण उनकी अनुपस्थिति में ए. बालसुब्रमण्यम पढ़कर सुनाते हैं. (इस भाषण के कुछ अंश इस अंक में अन्य स्थान पर पढ़िये).

केरल पर

पी. राममूर्ति केरल की वामपंथी-जनवादी सरकार का अभिवादन करते हुए एक प्रस्ताव पास करते हैं. इस प्रस्ताव में केरल सरकार द्वारा आम जनता के विभिन्न वर्गों को राहत दिलाने वाले कदमों की तारीफ की गई है. प्रस्ताव में मजदूर वर्ग व ट्रेड यूनियनों को आह्वान किया गया है कि वे इस सरकार का पुरजोर समर्थन करें व इसे गिराने के षड़यंत्रों का मुकाबला करें. सदस्यों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध करते हुए राममूर्ति ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 30 वर्ष के अपने अस्तित्व में उन मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचा जो उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं. अर्थव्यवस्था को सही मानों में यही लोग संभालते हैं जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफों की मांग कर रही हैं मजदूरों से उनके ट्रेड यूनियन अधिकार तक छीने जा रहे हैं. देश की जनता की समस्याओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व केरल की सरकारें अपनी सीमाओं के बावजूद महत्त्वपूर्ण काम कर रही हैं. नीरेन घोष प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. वे कहते हैं कि इन तीन राज्यों में मजदूर वर्ग ने जो कुछ पाया है वह देश के सारे मजदूर वर्ग के लिए आदर्श है. इसके बाद जनरल काउंसिल सर्व-सम्मति से प्रस्ताव पास करती है.

त्रिपुरा पर

समर मुखर्जी, जिन्होंने हाल ही में ई. बालानंदन के साथ त्रिपुरा का दौरा किया, त्रिपुरा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं. इसमें त्रिपुरा में हाल ही में हुए नृशंस हत्याकांड की निंदा की गई है जिसमें 522 व्यक्तियों की जानें गई व 1.96 लाख लोग बेघरबार हो गए. यह हत्याकांड राष्ट्रविरोधी तत्वों ने करवाया और उनका इरादा इसके बहाने राज्य की वामपंथी सरकार को गिरवाना था. समर मुखर्जी ने बताया कि इस घटना के तत्काल बाद प्रतिक्रियावादी तत्वों ने हायतौबा मचानी आरंभ की और त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई. किंतु त्रिपुरा सरकार ने सफलतापूर्वक उपजाति युवा समिति, आम्र-बंगाली तथा अन्य प्रतिक्रियावादी तत्वों के षड्यत्रों को बेनकाब कर दिया. सरकार को बंगालियों व त्रिपुरियों दोनों

का ही विश्वास प्राप्त है. संयुक्त प्रदर्शनों, सभाओं आदि से साफ जाहिर है कि इन दोनों जातियों की बहुसंख्या प्रेम और सौहाद बनाए हुए है. हाल की इन दुःखद घटनाओं के बाद त्रिपुरा एक बार फिर आगे बढ़ रहा है और उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है. ई. बालानंदन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं. वे बताते है कि हाल के हत्याकांड में 2 से 5 वर्षों तक के बच्चों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए. अपनी-अपनी जातियों के नाम पर ये गुमराह व्यक्ति निहित स्वार्थों की सेवा कर रहे हैं. राष्ट्रीय एकता की खातिर त्रिपुरा सरकार व जनता के संघर्ष का अभिवादन करते हुए एन. प्रसाद राव प्रस्ताव के लिए समर्थन की अपील करते हैं. प्रस्ताव को सर्वसम्मत समर्थन मिलता है. इसमें त्रिपुरा के साथियों को इस बात पर मुबारकबाद दिया है कि उन्होंने विभिन्न जातियों में संकीर्णता व पारस्परिक नफरत पैदा करने की पुरजोर कोशिशों का डटकर मुकाबला किया और मजदूर वर्ग व ग्राम जनता की वर्ग चेतना को कुंद न होने दिया. प्रस्ताव में केंद्रीय सरकार से कहा गया है कि वह इस दुर्घटना से पैदा हुई दिक्कतों का सामना करने के लिए तुरंत त्रिपुरा सरकार को हर संभव सहायता दे. इसमें यूनियनों का भी आह्वान किया गया है कि वे सरकार को इस नाजुक समय में पूरा समर्थन दें.

पश्चिम बंगाल पर

पी. के. कुरणे पश्चिम बंगाल पर प्रस्ताव रखते हैं. पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार के नेतृत्व में मजदूरों, किसानों व ग्राम जनता की उपलब्धियों को बताते हुए प्रस्ताव में कुछ निहित स्वार्थों द्वारा इस सरकार को गिराने के प्रयत्नों का पर्दाफाश किया गया है. प्रस्ताव में मजदूर वर्ग को आगाह किया है कि वह इन षड़यंत्रों के प्रति चौकस रहें, एक-पार्टी शासन व अधिनायकवाद के खिलाफ व्यापक मंच बनाए जाने में सहयोग करें तथा जनतंत्र व ग्राम जनता के वास्ते बेहतर जीवन स्तर मुहय्या करने के लिए संघर्षरत पश्चिम बंगाल सरकार की हर कीमत पर रक्षा करें. प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मनोरंजन राय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मेहनत कश लोगों के हित में लिए गए कदमों का विवरण दिया. उन्होंने कांग्रेस (इ.) द्वारा गड़बड़ पैदा करके वामपंथी सरकार को गिराने के प्रयत्नों का भंडाफोड़ किया. जनरल काउंसिल ने इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया.

रिपोर्ट

चाय के समय के बाद बैठक फिर शुरू होती है. जनरल काउंसिल के 200 सदस्य इसमें उपस्थित हैं. वर्किंग कमेटी की ओर से एम. के. पंधे ने एक प्रस्ताव कमेटी व एक क्रीडेंशिल कमेटी गठित करने का सुझाव दिया. प्रस्ताव कमेटी के संयोजक के पद के लिए नृसिंह चक्रवर्ती तथा तथा सदस्यों के रूप में एन. प्रसाद राव, नीरेन घोष, बीरेन राय, पी. के. कुरणे तथा रवींद्रनाथ के नामों का सुझाव है. इसी प्रकार क्रीडेंशल कमेटी में संयोजक के रूप में ए. नल्लसिवन तथा सदस्यों के रूप में शांति घटक, एस. सूर्यनारायण राव, काली घोष, विश्वेश्वर गांगुली और नबीराजन के नाम के नाम प्रस्तावित किये जाते हैं. इन समितियों का सर्वसम्मति से चुनाव हो जाता है. बैठक वर्किंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित जनरल काउंसिल के कार्यक्रम को भी पारित कर देती है.

सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति जनरल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. वे सीटू की मद्रास कांफ्रेंस के बाद के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करते हैं. (उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश इसी अंक में प्रकाशित किए जा रहे हैं.)

12 **सितंबर** : इस सेशन की अध्यक्षा सुशीला गोपालन हैं. सीटू सचिव एम. के. पंधे संगठन व इसकी गतिविधियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. (उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश भी इस अंक में प्रकाशित किए गए हैं.)

बहस

महासचिव व सचिव की रिपोर्टों पर बहस आरंभ होती है. उपाध्यक्ष मनोरंजन राय, के रमणी तथा सी. कन्नन बारी-बारी से अधिवेशन की कार्रवाई को निर्देशित कर रहे हैं. पहले दिन की बहस में अमल घोष दस्तिदार (असम), के. एन. रवींद्रनाथ (केरल), बीरेन राय (पश्चिम बंगाल), मनोरंजन राय (पश्चिम बंगाल), ई. जे. के. नायर (कर्नाटक), हरसहाय सिंह (उत्तर प्रदेश), श्रद्धानंद सोलंकी (हरियाणा), जे. एस. लायलपुरी (पंजाब), एन. पद्मालोचन (केरल), नीरेन घोष (पश्चिम बंगाल), चंडी प्रसाद (बिहार), पी. के. कुरणे (महाराष्ट्र), पारसा सत्यनारायण (आंध्र प्रदेश), जय गोपाल (पश्चिम बंगाल), हरिकृष्ण साहा (गुजरात), टी. एन. सिंह (बिहार), परिमल मित्रा (पश्चिम बंगाल), शिवाजी पटनायक (उड़ीसा), रामभट्ट मुखर्जी (पश्चिम बंगाल), एस. एस. भट्टाचार्य (मध्य प्रदेश), चित्तव्रत मजूमदार (पश्चिम बंगाल), ए. नल्लसिवन (तमिलनाडु), एस. सूर्यनारायण राव (कर्नाटक), मोती लाल शर्मा (मध्य प्रदेश), शांति घटक (पश्चिम बंगाल) तथा बालन दास (आंध्र प्रदेश) भाग लेते हैं.

13 **सितंबर : बहस जारी है.** इस दिन बहस में भाग लेते हैं—सी. बी. सी. वारियर (केरल), ए. दक्षी (पश्चिम बंगाल), सुशील भट्टाचार्य (दिल्ली), पी. पी. सांजगिरी (महाराष्ट्र), पी. गंगाम्मा (पश्चिम बंगाल), के. के. राय गांगुली (पश्चिम बंगाल), कृष्ण कांत वर्मा (राजस्थान) तथा सूरज भान भारद्वाज (दिल्ली). इस प्रकार दो दिनों की बहस में 34 सदस्यों ने भाग लिया. रिपोर्ट के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए व कई जरूरी मुद्दे उठाए. उन्होंने अपने-अपने राज्यों में हुए संघर्षों की भी समीक्षा की. वे कई सुझाव देते हैं व अपनी सीमाएं व दिक्कतें बताते हैं. कई सदस्य अनुरोध करते हैं कि उनके राज्यों में ट्रेड यूनियन स्कूल आयोजित किए जाएं. प्रबंध में मजदूरों की भागेदारी के बारे में वे कहते हैं कि यह मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ाने व उनके आंदोलनों को खत्म करने की एक चाल है. कुछ सदस्य विचार व्यक्त करते हैं कि असंग-

ठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने के लिए और ध्यान देना होगा. एक सदस्य ने कहा कि एकाधिकारी घराने आर्थिक संकट का भार मजदूर वर्ग के साथ-साथ छोटे उद्योग पर भी डालने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए ट्रेड यूनियन आंदोलन को छोटे स्तर के उद्योगों की मांगों का भी समर्थन करना चाहिए.

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि मजदूर वर्ग की फौरी समस्याओं पर प्रत्येक उद्योग में देशव्यापी स्तर पर आंदोलन छेड़ने चाहिए. मूल्य-वृद्धि, बेरोजगारी, अधिनायकवाद आदि के खिलाफ संघर्ष इस प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आंदोलन तैयार किया जा सकता है. कई साथियों ने इससे पहले प्रत्येक उद्योग का एक सम्मेलन बुलाने की जरूरत पर बल दिया. कई ऐसे राज्यों जहां ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर है के सदस्यों ने सीटू केंद्र से अधिक सहायता की मांग की. सदस्यों ने असम के पृथकतावादी आंदोलन तथा वामपंथी मोर्चों द्वारा शासित तीन राज्यों में कुछ निहित स्वार्थों द्वारा जनता-विरोधी कार्रवाइयां किए जाने की निंदा की. उन्होंने इन सरकारों की उपलब्धियों को ग्राम जनता में प्रचारित करने तथा देशभर के मजदूरों, किसानों व ग्राम जनता को इन सरकारों की रक्षा करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया.

जवाब

महासचिव पी. राममूर्ति बहस का जवाब देते हैं. वे कई मुद्दों की विस्तार से चर्चा करते हैं. वे कहते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का सर्वप्रमुख काम अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष करना है. अधिनायकवाद के खिलाफ होने वाले संयुक्त संघर्षों का फायदा आखिर में मजदूर वर्ग को ही होगा बुर्जुआजी को नहीं. वामपंथी मोर्चा सरकारों की भूमिका के बारे में बोलते हुए राममूर्ति ने कहा कि हम उन्हें आदर्श सरकारों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं. प्रबंध में मजदूरों की भागेदारी के बारे में सीटू का मत स्पष्ट करते हुए राममूर्ति ने कहा कि हम इसे तभी स्वीकार कर सकते हैं जब कि भीगेदारी हर स्तर पर हो. दूसरे शब्दों में भागीदारी केवल उत्पादन के स्तर पर ही नहीं बल्कि बिक्री, खरीदारी, कारखाने में प्रयोग होने वाली तक्नालिजी के चयन आदि सभी स्तरों पर हो. उन्होंने खेतिहर मजदूरों को संगठित करने के लिए सामूहिक राशि एकत्र करने की जरूरत पर बल दिया. राममूर्ति ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों के आंदोलन को तत्कालीन राजनीतिक दशा को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया था. अब जब मजदूर वर्ग पर हमले बढ़ रहे हैं इस संघर्ष को दुबारा शुरू करना जरूरी है. उन्होंने सीटू द्वारा प्रस्तावित मजदूर शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला. अंत में कई अन्य विषयों पर स्पष्टीकरण देते हुए राममूर्ति ने कहा कि हम दिल्ली में बन रहे सर्वदलीय कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसमें ट्रेड यूनियन, महिला संगठनों, छात्रों व युवकों को मिलाकर एक विशाल मंच बनाया जाना और जनता की जरूरी समस्याओं पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाना है. यदि किन्हीं कारणों से यह मंच नहीं बन पाता तो सीटू सचिवालय अलग रूप से इन मुद्दों पर आंदोलन छेड़ने का आह्वान करेगा और इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा.

कामगार महिलाओं पर

अब सीटू उपाध्यक्ष सुशीला गोपालन, मंच पर आती हैं. वे देश में कामगार महिलाओं की दुर्दशा बयान करती हैं. वे एक सर्वेक्षण का हवाला देती हैं जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भी कामगार महिलाओं की संख्या 11.3 से घटकर 9.1 रह गई है. आर्थिक संकट के कारण महिलाओं को अनियमित कार्य-अवधि वाले कामों को भी स्वीकार करना पड़ रहा है. वे सुझाव देती हैं कि नवंबर में कामगार महिलाओं का एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए. वे कामगार महिलाओं की समस्याओं पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं. प्रस्ताव में कहा गया है कि मजदूर वर्ग को कामगार महिलाओं की मांगों के समर्थन में तथा उनके खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में आंदोलन तैयार करना चाहिए. यह काम बहुत जरूरी है. शिबानी सेनगुप्त ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि औरतों से असंगठित क्षेत्रों में सस्ते मजदूर के रूप में काम लिया जाता है. उन्होंने बैठक से अपील की कि कामगार महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए. प्रस्ताव पर पी. राममूर्ति, बालाजीदास, बी. पी. कश्यप तथा ई. जे. के. नायर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं.

समर मुखर्जी 1979 के वर्ष का लेखा प्रस्तुत करते हैं.

रेल कर्मियों पर

नृसिंह चक्रवर्ती लोको रनिंग स्टाफ को मुबारकबाद भेजने व उनके न्यायोचित संघर्ष में सीटू की ओर से उनको पूरा समर्थन देने का प्रस्ताव पेश करते हैं. साथ ही वे रेलवे मजदूरों के संघर्ष में सीटू की ओर से एकजुटता के इजहार का एक अन्य प्रस्ताव भी रखते हैं. इस प्रस्ताव में 1974 की रेलवे मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल के समय के उठे हुए मुद्दों पर मंत्रालय के उदासीन रवैये पर चिंता व्यक्त की गई है. प्रस्ताव में अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे रेलवे मजदूरों को पूरे समर्थन का आश्वासन दिया गया है. एम. एम. लारेंस इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं.

असम पर

समर मुखर्जी असम पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं. वे असम की वर्तमान हालत की विस्तार से व्याख्या करते हैं. प्रस्ताव देश के मजदूर वर्ग को ध्यान दिलाता है कि इस क्षेत्र की घटनाओं तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के नये आक्रामक इरादों के बीच सीधा संबंध है. अमरीकन साम्राज्यवादियों की एशिया

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

"मजदूर वर्ग को देश का नेतृत्व करना है"

—पी. राममूर्ति

कन्नानोर में सितंबर 11-14 को हुई सीटू जनरल काउंसिल की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सीटू महासचिव पी. राममूर्ति ने कहा, "वक्त बीता जा रहा है. मजदूर वर्ग को साम्राज्यवाद के खिलाफ व शांति, आजादी, जनतंत्र व समाजवाद का पक्ष लेते हुए देश का नेतृत्व संभालना है".

सीटू की मद्रास कांफ्रेंस के बाद से अब तक देश में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करते हुए राममूर्ति ने बतलाया कि अधिनायकवादी रुख तथा जनवादी ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों का दौर फिर शुरू हो गया है. कांग्रेस (इ.) के कुछ केंद्रीय मंत्रियों द्वारा पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार को धमकियां दिये जाने का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि संसदीय पद्धति को खत्म करने व उसके स्थान राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किये जाने की मांग अधिनायकवादी खेमे से आनी शुरू हो गई हैं और ये देश के लिए अमंगल की सूचना हैं.

निर्देशित सिद्धांत : मूलभूत अधिकारों व निर्देशित सिद्धांत पर हो रही चर्चा के बारे में बात करते हुए राममूर्ति ने मशहूर केशवानंद भारती केस का उदाहरण दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के संदर्भ में फैसला दे दिया है कि संविधान के बुनियादी चरित्र को नहीं बदला जा सकता. उन्होंने कहा यदि सरकार राज्य के निर्देशित सिद्धांतों (जैसे रोजगार देना, रोजगार न मिलने तक बेरोगारी भत्ता देना, सही मजदूरी देना आदि) को लागू करने के लिए सही मानों में चिंतित हैं तो वह इन सिद्धांतों में बुनियादी अधिकारों की सूची में क्यों नहीं डाल देती ?

मजदूर वर्ग विरोधी: पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए राममूर्ति ने ऐसे अनेकों उदाहरण दिये जिनमें पुलिस ने समाज के कमजोर वर्गों मेहनतकशों व महिलाओं पर जुल्म ढाए हैं. केंद्र व राज्य में शासन कर रही कांग्रेस (इ) सरकारों ने तो अपने मेहनतकश-विरोधी रुख का आभास तो पहले से ही दे रखा है.

बी.पी.ई.: ब्यूरो आफ पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की भूमिका की निंदा करते हुए राममूर्ति ने टिप्पणी की : "सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में सार्वजनिक धन में हेराफेरी, भ्रष्टाचार व अपव्यय पर बी.पी.ई. आंखें मूंदे पड़ा रहता है··· किंतु इस क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं पर यह नजरें जमाये रखता है व जरा भी बढ़ने नहीं देता. इसने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों के प्रबंधकों को निर्देश दे रखा है कि ट्रेड यूनियनों से कोई ऐसा नया समझौता न किया जाए जिसका कोई आर्थिक पहलू हो. इसके परिणामस्वरूप कई इकाइयों में मजदूरों को चप्पलें, कपड़े इत्यादि ऐसा कोई सामान देने से भी मना कर दिया जाता है भले ही वह उनके काम, कार्यकुशला या सुरक्षाके लिए आवश्यक हो." उन्होंने होटल कार्पोरेशन आफ इंडिया व भारत हैवी प्लेट्स के उदाहरण दिए जहां बी.पी.ई. ने समझौतों को लागू होने से रोक दिया है.

ठेका मजदूर : राममूर्ति ने बताया कि ठेका मजदूर संबंधी कानून का सबसे अधिक उल्लंघन सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है और यह भारत सरकार की खुली जानकारी में हो रहा है. अनेकों सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में स्थाई किस्म के काम को भी ठेकेदारों को सौंप दिया जाता है और इससे मजदूर पिसते हैं. केंद्रीय कृषि व सिंचाई मंत्री ने खुले रूप से संसद में कह दिया है कि हम ठेका पद्धति को समाप्त नहीं करेंगे. क्योंकि इसके द्वारा हमें मजदूर सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, इस्ट्रूमेंटेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जहां पांच महीनों के लिए 90 प्रतिशत से अधिक मजदूर ठेका मजदूर के रूप में काम करते हैं, तथा दिल्ली के हस्पतालों में जूनियर डाक्टरों की हड़ताल का हवाला देते हुए राममूर्ति ने कहा कि केंद्रीय श्रममंत्री ने मंत्रिमंडल को सुझाव भेजा था कि स्थाई किस्म के पदों पर स्थायी नियुक्तियां ही होनी चाहिए. किंतु मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया.

बोनस : बोनस एक्ट के संबंध में राममूर्ति ने बताया कि श्रम मंत्रालय के सभी सुझाव, जैसे बोनस की सीमा हटा देना तथा सुप्रीम कोर्ट फैसले के अनुसार सभी प्रकार की नौकरियों में बोनस ऐक्ट लागू करना, को मंत्रिमंडल ने नामंजूर कर दिया. मंत्रिमंडल ने केवल इतना माना है कि 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस एक्ट में स्थायी रूप से शामिल कर दिया जाए. राममूर्ति ने कहा कि सरकार इतना भी करने को तैयार न होती यदि उसे इस मुद्दे पर मजदूर वर्ग के प्रतिरोध का डर न होता.

अध्यादेश : राममूर्ति ने कहा कि ऐसा समझा जाता है कि केंद्रीय श्रम मंत्री यूनियन की मान्यता का मामला गुप्त मतदान से निश्चित करने और इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में संशोधन के पक्ष में थे किंतु सरकार ने इंटक को मदद पहुंचाने के लिए इस जनतांत्रिक मांग को भी ठुकरा दिया. इस सरकार का मजदूर विरोधी व जनवाद-विरोधी चरित्र तब और सामने आ जाता है जब हम पिछले कुछ महीनों में जारी किए गए अनेक अध्यादेशों को देखते हैं. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा व स्वयं केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का हवाला देते हुए राममूर्ति ने कहा : "इस प्रकार के कदमों को उठाने का असली उद्देश्य मेहनतकश लोगों द्वारा छेड़े जा रहे संघर्षों को दबाना है."

निर्भरता : आवश्यकता की वस्तुओं के बाजार से गायब हो जाने या इनकी कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बारे में राममूर्ति ने बताया : "भारतीय अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है. इसका मुख्य कारण पहले कांग्रेस सरकार और बाद में कुछ वर्षों के लिए सत्तारूढ़ जनता सरकार की जनविरोधी नीतियां हैं." 14 सौ करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था, जो इस वर्ष के अंत तक इससे दुगुनी हो जाएगी, की चर्चा करते हुए राममूर्ति ने विचार व्यक्त किया : "विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक पर हमारी निर्भरता बढ़ी है. आजादी के बाद यह पहला मौका है कि हमारे बजट में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी विनियोग के लिए यूरोपीय देशों के व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने का प्रावधान है." इसके फलस्वरूप एकाधिकारी घरानों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक रियायतें देनी पड़ रही हैं. संसद में सरकार द्वारा औद्योगिक नीति पर दिया गया बयान इसकी पुष्टि करता है.

नीति संबंधी वक्तव्य : सरकार द्वारा अपनी नीतियों पर दिए गए वक्तव्य की चर्चा करते हुए राममूर्ति ने बतलाया कि यह झूठे आश्वासनों व उपदेशों से भरा हुआ है. इसमें कहा गया है कि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करेगी, एकाधिकारी रुझानों व सम्पत्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करेगी, ऐसे उपाय करेगी जिससे औद्योगीकरण का लाभ आम आदमी को मिले इत्यादि. किंतु जब इन उपदेशों को अमलीजामा पहनाने का सवाल आता है तो सरकार फिर बड़े उद्योगों को उत्पादित मात्रा बढ़ाने व नये उद्योग शुरू करने का लाइसेंस सहर्ष दे देती है. यदि बड़े घरानों को उत्पादित मात्रा बढ़ाने की छूट दे दी जाती है तो छोटे उद्योगों को उत्पादन करने व मंडी में ठहरने का मौका ही कैसे मिल सकता है ? यह अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकारी घरानों व बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के तरीके हैं. वक्तव्य में ऐसी इकाइयों के लिए छूट देने की बात कही है जो केवल निर्यात के लिए सौ प्रतिशत उत्पादन कर सकते हैं. इस स्तर का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही कर सकती हैं. राममूर्ति ने आगे कहा कि यह नीति-संबंधी वक्तव्य संसद में केवल प्रस्तुत भर कर दिया गया तथा इस पर विचार-विमर्श करने का कोई मौका नहीं दिया गया. अब इसे लागू कर दिया गया है. इन नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट को दूर करने का तरीका भी मुश्किलों में फंस गया है. इस सबके परिणाम स्वरूप छंटनी व बेरोजगारी की मात्रा में वृद्धि होगी.

प्रबंध में भागेदारी : पी. राममूर्ति ने जुलाई में प्रधानमंत्री द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत का जिक्र किया. प्रबंध में भागेदारी के सवाल पर सीटू महासचिव ने कहा कि हम भागेदारी के लिए तैयार हैं बशर्ते कि यह भागेदारी ऊंचे प्रबंधकीय स्तर से लेकर नीचे माल बेचने के स्तर तक हो. यदि ऐसा नहीं होता तो यह भागीदारी [illegible] हो जाती है और इसके पीछे असली मंशा मजदूरों का और अधिक शोषण करने की होती है. सरकार व मालिकान इस प्रकार की भागेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनके द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार व अनियमितताएं जनता के सामने आ जाती हैं. दरअसल भागेदारी के सिद्धांत को उछालने के पीछे असली इरादा मजदूरों के ऊपर काम के बोझ को बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं है. हमें इस बारे में अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना चाहिए.

संघर्षों का नेतृत्व : पालेकर अवार्ड की चर्चा करते हुए राममूर्ति ने कहा कि सीटू इस अवार्ड के विरुद्ध समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के पत्रकारों व कर्मचारियों के आंदोलन को पूरा समर्थन देती है. उनका विचार था : "ट्रेड यूनियन आंदोलन को तमाम मेहनतकशों को लामबंद करने व संघर्षों में उनका नेतृत्व करने को तैयार करना होगा. अधिनायकवाद के रुझान तथा जनवादी अधिकारों पर हमले होने के रुझान को रोकने के लिए यह आवश्यक है."

समर्थन: कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार तथा अन्य राज्यों में चल रही हड़ताल व अन्य संघर्षों के सिलसिले में राममूर्ति ने बताया कि महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के विरुद्ध चेतना पैदा करना भी जनवादी आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है. हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मजदूर वर्ग द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाने से न केवल हरिजनों व अन्य पिछड़े वर्गों को शक्ति मिलेगी बल्कि मजदूर वर्ग व खेतिहर मजदूर की एकता का सुदृढ़ आधार भी बन पाएगा. इसी प्रकार मजदूर वर्ग को उपज के लिए सही कीमत मिलने तथा ऋणग्रस्तता से छुटकारा पाने की किसानों की मांगों का समर्थन करना चाहिए.

मूल्य वृद्धि: मूल्य वृद्धि के खिलाफ बन रहे आंदोलन में राममूर्ति ने निम्न नारों का सुझाव दिया—आवश्यकता की वस्तुओं का थोक व्यापार सरकार अपने हाथों में ले, जनसमितियों के निरीक्षण में प्रभाव शाली सार्वजनिक वितरण पद्धति बनाई जाए, किसानों को उपज का सही मूल्य मिले तथा इन वस्तुओं का बिक्री मूल्य न बढ़ाया जाए. इन कदमों को उठाए बिना मूल्यवृद्धि को कम करने की बात करना अपने आपको व जनता को छलाये में रखना मात्र है.

साम्प्रदायिक झगड़े: देश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक झगड़ों की चर्चा करते हुए राममूर्ति ने कहा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का यह कर्त्तव्य है कि वह सभी धर्म-निरपेक्ष व जनवादी ताकतों को पुरजोर समर्थन दे व उन संकीर्णतावादी ताकतों को दबाने में अपना योगदान दे जो धर्म अथवा जाति के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं.

उत्तर-पूर्व: सीटू महासचिव ने कहा कि 'विदेशियों' के नाम पर असम तथा उत्तर-पूर्व के कुछ अन्य राज्यों में

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

रेलकर्मी मांग दिवस मनाएंगे

आल इंडिया रेलवेमैंज फेडरेशन के 28 से 31 अगस्त को बीकानेर में हुए सालाना सम्मेलन ने वेतन में समानता, आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं, रेलकर्मियों को 8.33% कानूनी बोनस, वेतन में समानता मिलने तक 150 रुपये अंतरिम सुविधा आदि की मांगों सहित एक 10 सूत्री मांगपत्र तैयार किया है और समूचे देश में 19 सितंबर को शहीद दिवस तथा 28 नवंबर को मांग दिवस मनाने का फैसला किया है. सम्मेलन में उमराओमल पुरोहित को अध्यक्ष तथा जे. पी. चौबे को पुनः महासचिव चुना गया है.

नई दिल्ली में 20 सितंबर को कई केटेगरी वाइज एसोसिएशनों जैसे ए. आई. सी. एंड डब्लू. एस. सी., ए. आई. टी. डब्लू. ए., ए. आई. एस. सी. एंड टी. एस. ए. के घटकों तथा एन. एफ. रेलवे की यू. सी. आर. व एस. ई. रेलवे का जेड. सी. सी. आर. की एक बैठक में वेतन में समानता, कानूनी बोनस, डीकेजुअलाइजेशन, समूचे ट्रेड यूनियन अधिकारों, समझौता वार्ताओं के लिए यूनियनों के प्रतिनिधित्व तय करने आदि की मांगों को लेकर एक 16 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है. यह तय किया गया है कि 21 से 27 नवंबर के दौरान अभियान सप्ताह मनाया जाएगा तथा 8 दिसंबर को उपरोक्त मांगपत्र जनसमूहों के द्वारा डिविजनल रेलवे मैनजरों के माध्यम से रेलवे अधिकारियों को दिया जाएगा.

15 अक्तूबर को महाराष्ट्र बंद

राज्य में बिगड़ती कानून व व्यवस्था, समाज के कमजोर तबकों पर जुल्म तथा कीमतवृद्धि के खिलाफ कई राजनीतिक दलों और सीटू सहित कई ट्रेड यूनियनों ने 2 अक्तूबर को गिरफ्तारियां देकर और आदेशों का उल्लंघन करके सत्याग्रह करने तथा 15 अक्तूबर को राज्य बंद करने का आह्वान किया है.

आंध्र प्रदेश में संपूर्ण बंद

आल पार्टीज एक्शन काउंसिल के आह्वान पर राज्य की जनता ने विजयवाड़ा में 16 सितंबर को एक जबरदस्त रैली में भाग लिया और 24 सितंबर को राज्य बंद का आयोजन किया. इस दिन राज्य में संपूर्ण बंद रहा. मांगें थी —सभी मजदूरों व गरीब तबके के लोगों के बकाया खत्म करना, कृषि उपज के अच्छे दाम देना, कीमत नियंत्रण और जरूरी चीजों का उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाना. काउंसिल ने यह भी फैसला किया है कि यदि इन मांगों के प्रति सरकार ने कुछ नहीं किया तो 10 नवंबर से टक्स नहीं अभियान व जरूरी चीजों की जमाखोरी खत्म करने के लिए भी यह जनता को एकजुट करेगी.

समाचार-पत्र-कर्मचारियों की 30 सितंबर को हड़ताल

सरकार द्वारा मालिकान और कर्मचारियों के साथ बुलाई गई दो दिन की अनौपचारिक वार्ता के नाकामयाब होने के तुरंत बाद नेशनल कनफेडरेशन आफ न्यूजपेपर्स एंड न्यूजएजेंसी एंप्लाईज आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, एस. वाई. कोल्हात्कर ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की कि समूचे देश के समाचार पत्र कर्मचारी अपनी मांग कि सरकार पालेकर ट्रिब्यूनल की अंतिम सिफारिशों में संशोधन करे के समर्थन में 30 सितंबर को हड़ताल करेंगे ताकि समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ जिन्होंने उचित वेतन संशोधन के लिए 13 सालों तक इंतजार की है, न्याय किया जा सके.

जनवादी चीन को शुभकामनाएं

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस और सीटू मजदूर चीन की जनता और मजदूर वर्ग को चीनी क्रांति की 31वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं.

सी. आई. टी. यू. चीन के मजदूर वर्ग व जनता को क्रांति के बाद आर्थिक नजरिये से पिछड़े देश को, जहां उत्पादन के सामंती और पूर्व-पूंजीवादी संबंध हावी थे, समाजवादी देश में बदल कर समाजवादी निर्माण में, आर्थिक योजनाओं, उद्योग, कृषि, विज्ञान, शिक्षा और तकनीकी में सराहनीय उपलब्धियों के लिए बधाई देती है.

सी. आई. टी. यू. आल चाइना फेडरेशन आफ लेबर को हार्दिक शुभकामनाएं भेजती है और आर्थिक तौर पर पिछड़े चीन को एक आधुनिक, उन्नत समाजवादी चीन में बदलने के लिए कठिन संघर्ष में इसकी गतिविधियों को तहेदिल से संपूर्ण सफलता की कामना करती है तथा आशा करती है कि भारत और चीन में संबंध जीवन के हर क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहेंगे.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र
एक प्रति की दर पचास पैसे
वार्षिक चंदा छः रुपये
मिलने का पता :
सीटू कार्यालय
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

"मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए"

—एम. के. पंधे

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने 11 से 14 सितंबर को कन्नानोर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल की बैठक में संगठन व कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की. अपनी रिपोर्ट में पंधे ने कहा कि मद्रास कांफ्रेंस से जनरल काउंसिल के बीच के दौरान मजदूर वर्ग ने पूंजीपतियों व सरकार के हमलों के बावजूद अनेक संयुक्त संघर्ष चलाए. मद्रास कांफ्रेंस ने संगठन के सामने कई प्रकार के लक्ष्य व कार्यक्रम रखे थे. इनको पूरा करने के लिए सीटू केंद्र, राज्य समितियों, उद्योग-स्तर के संगठनों व संबद्ध यूनियनों को काफी परिश्रम करना पड़ा.

जनरल काउंसिल की बैठक बुलाए जाने में हुई देरी की चर्चा करते हुए सीटू सचिव ने गत मार्च में नई दिल्ली में हुई वर्किंग कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों तथा इसके द्वारा 21 अप्रैल को 'मांग दिवस' के रूप में मनाए जाने के आह्वान पर हुई अच्छी प्रतिक्रिया के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि कई यूनियनों ने सीटू केंद्र लिखा को है कि मजदूर वर्ग व जनता की आम समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के दिवस नियमित रूप से मनाए जाने चाहिये.

विभिन्न उद्योगों के स्तर पर हो रही गतिविधियों के बारे में एम. के. पंधे ने कहा कि हम उद्योग-स्तर की बैठकों में साथियों द्वारा उठाए गए मुद्दों व मांगों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए हैं. इसका कारण यह है कि हमारे पास साधनों व इन उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करने योग्य सक्रिय कार्यकर्ताओं की कमी है. इन कमियों के बावजूद सीटू केंद्र ने जो भी संभव हो सका है किया है. इसके बाद एम. के. पंधे ने मद्रास कांफ्रेंस के बाद के समय में उद्योग स्तर पर हुई गतिविधियों की समीक्षा की.

इस्पात : इस्पात उद्योग में हो रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए सीटू सचिव ने बताया कि इस क्षेत्र में प्रबंधकों व मजदूरों में समझौता हो गया था. किंतु समझौते पर हस्ताक्षर होते ही प्रबंधकों ने सभी केंद्रों को गुप्त संदेश भेजा जिसमें उन्हें निदेश दिया गया था कि मजदूरों को एक वर्ष तक केवल रु० 375/- का भुगतान किया जाय. किंतु सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एकजुट प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रबंधकों को वह सर्कूलर वापिस ले लेना पड़ा तथा नए भर्ती मजदूरों को भी पूरी राशि देनी पड़ी. इस प्रकार इन मजदूरों को समझौते के अनुसार उनकी नियुक्ति के दिन से ही पूरी मजदूरी मिलने लगी.

इस्पात उद्योग में काम कर रहे 75 हजार ठेका मजदूरों का भी सवाल उठाया जा रहा है. इस बारे में निश्चय किया गया है कि सारे देश में इस्पात उद्योग में काम कर रहे इन ठेका मजदूरों की मांगो का एक विस्तृत मांगपत्र तैयार किया जाए और इन मांगों पर एक संयुक्त आंदोलन चलाया जाए. उन्होंने बताया कि सीटू केंद्र द्वारा किए गए आह्वान पर इस्पात के मजदूरों ने 'सीटू संघर्ष कोष' में एक लाख 78 हजार रुपये एकत्र किए.

कोयला : इस्पात उद्योग की भांति कोयला उद्योग में भी संगठन व गतिविधियों के स्तर पर सीटू ने संतोषजनक प्रगति की है. कोयला उद्योग में हुए संघर्ष व उसके बाद प्रबंधको व मजदूरों के बीच हुए समझौते का हवाला देते हुए सीटू सचिव ने बताया कि पहले तो प्रबंधक मजदूरों को धमकी दे रहे थे कि उनकी हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा तथा यदि आवश्यकता हुई तो सेना का प्रयोग भी किया जाएगा. किंतु बाद में सरकार को मजदूरों के साथ समझौता करना पड़ा जिसके तहत न्यूनतम मजदूरी 512 रु. निर्धारित हो गई तथा हर मजदूर को कम से कम 73.90 रु. की वेतनवृद्धि मिली. उन्होंने जनरल काउंसिल को यह भी बताया कि कोयला उद्योग में सीटू यूनियनों ने 'सीटू संघर्ष राशि' में 22,751 रु. दिए हैं.

जूट : जूट मजदूरों के संघर्षों की समीक्षा करते हुए पंधे ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बाहर भी इस उद्योग में सीटू की गतिविधियां बढ़ रही हैं. साथ ही में अखिल भारतीय स्तर पर जूट मजदूरों की एक फेडरेशन बनने से कमजोर राज्यों में गतिविधियां बढ़ाने व समन्वित करने में मदद मिलेगी. बंगाल चटकल मजदूर यूनियन के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए पंधे ने बताया कि इस समय यह संस्था अधिक बोनस मिलने के लिए संघर्ष का नेतृत्व कर रही है.

भेल : इस वर्ष के शुरू में भेल में हुए समझौते की चर्चा करते हुए पंधे ने कहा कि मजदूरी में असंगतियों के सवाल पर फैसला नहीं हुआ है और इस सवाल पर बैठाइ गई उपसमिति इस पर विचार कर रही है. भेल के मजदूरों के संघर्षों के बारे में चर्चा करते हुए पंधे ने बताया कि झांसी में हुए ऐसे ही एक संघर्ष में का. बुद्धिवाल शहीद हो गए. कई अन्य साथियों को फौजदारी के मामलो में फंसाया गया है. सीटू ने प्रबंधकों की बदला लेने वाली नीति का विरोध किया है. इसने उन अफसरों को भी अपना पूरा समर्थन दिया है जिन्हें सीमेंस के साथ किए जा रहे गलत समझौते का विरोध करने के कारण विक्टिमाइज किया गया है.

एच. एस. सी. एल. : इस उद्योग में सीटू के समर्थक सबसे अधिक संख्या में हैं. यहा कई हजार स्थायी मजदूरों को अतिरिक्त घोषित कर दिया गया है और किसी भी समय उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है. ठेका मजदूरों को नौकरी सुरक्षा दिलवाने के सवाल को सीटू ने उठाया है. भिलाई में इस पर एक लंबा संघर्ष भी चला.

सीमेंट : सीमेंट उद्योग के बारे में

एम. के. पंधे ने बताया कि कई सीमेंट यूनियनों ने सीटू से कहा है कि वह विभिन्न सीमेंट यूनियनों में एकता स्थापित करने के लिए पहलकदमी करें.

बीड़ी : बीड़ी मजदूरों की समस्याओं की चर्चा करते हुए सीटू सचिव ने कहा कि भारत सरकार ने बीड़ी वकर्ज वैलफेयर स्कीम के तहत एक सलाहकार समिति बनाने का निश्चय किया है. इस बारे में सीटू से कहा गया है कि वह इस उद्योग में अपनी सदस्य संख्या के आंकड़े प्रस्तुत करे.

गोदी, बंदरगाह व नाविक : इस मोर्चे पर काफी काम हो चुका है. सीटू सचिव ने इस उद्योग में वाटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन आफ इंडिया तथा फारवर्ड सीमैंज यूनियंज आफ इंडिया के नेतृत्व में हुए आंदोलनों का समीक्षात्मक विवरण दिया व इन यूनियनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों की यूनियनों से बिरादराना संपर्क बनाए जाने की चर्चा की. वाटर ट्रांस्पोर्ट वर्कर्ज फेडरेशन ने नाविकों व कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने का भी निर्णय किया है.

प्लांटेशन : प्लांटेशन मजदूरों के आंदोलन की चर्चा करते हुए एम. के. पंधे ने बताया कि भारत सरकार ने अब तक संसद के सामने प्लांटेशन लेबर (अमैंडमेंट) बिल नहीं रखा है हालांकि इस बारे में विभिन्न केंद्रीय श्रम मंत्रियों ने बार बार आश्वासन दिया है.

रेलवे : मद्रास कांफ्रेंस के बाद के समय में रेलवे में मजदूर आंदोलन आगे बढ़ा है और सीटू मजदूरों की मदद के लिए सदा तत्पर रही है. रेलवे के विभिन्न संघर्षों की चर्चा करते हुए सीटू सचिव ने बताया कि रेलवे की सभी गैर-मान्यताप्राप्त यूनियनों व कैटेगरी-वाइज एसोसियेशनों की एक समन्वय समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है जिससे कि रेलवे मजदूर एकजुट हो तथा अपनी आम समस्याओं को प्रचारित कर सकें. रेलवे में काम कर रहे ठेका मजदूरों में भी सीटू का काम बढ़ रहा है.

कामगार महिलाएं : कामगार महिलाओं में सीटू के काम की चर्चा करते हुए एम. के. पंधे ने कहा कि यह आवश्यक है कि सीटू की राज्य समितियां राज्यों की कामगार महिला समन्वय समितियों के काम में पूरी दिलचस्पी दिखाएं व उनकी सहायता करें. यूनियनों तथा राज्य समितियों में भी महिला साथियों को अधिक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए.

मूल्य सूचकांक : रथ कमेटी के सुझावों को सरकार द्वारा नामंजूर किए जाने के संदर्भ में सीटू सचिव ने आशा प्रकट की कि सीटू की पहलकदमी पर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एक मंच पर आ जाएंगे जिससे कि सरकार के इस मनमाने फैसले के खिलाफ व मूल्य सूचकांक को सुधारने के लिए आंदोलन किया जाए.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध : मद्रास में सीटू की चौथी कांफ्रेंस के बाद के समय में कई अन्य देशों की ट्रेड यूनियनों से सीटू के बिरादराना संबंध अधिक मजबूत हुए हैं और इस प्रकार हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक विस्तृत व गहन हो गए हैं. इस दौरान कई देशों के ट्रेड यूनियन प्रतिनिधिमंडलों ने भारत आकर सीटू से संपर्क स्थापित किया तथा सीटू ने भी कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजे.

सीटू व आइ. एल. ओ. : सीटू ने जून 1979 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 65वें अधिवेशन में भाग लिया. सीटू सचिव ने आई. एल. ओ. में 1980 में भेजे प्रतिनिधिमंडल के बारे में हुए विवाद की चर्चा की. उन्होंने आगे बताया कि सीटू को समुद्री मजदूरों के लिए आई. एल. ओ. द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है. सीटू समय-समय मजदूरों के ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों पर हो रहे हमलों के बारे में आइ. एल. ओ. को शिकायतें भेजती रहती है.

समितियां : सीटू सचिव ने ऐसी 20 समितियों के नाम गिनाए जिनमें सीटू को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है. अन्य 18 समितियों में सीटू के नुमांइदे सक्रिय हैं.

शिक्षा विभाग : एम. के. पंधे ने बताया कि सीटू के शिक्षा विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है. इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए कामरेड-शिक्षकों की आवश्यकता है.

सीटू प्रकाशन : सीटू सचिव ने पत्रिकाओं को बेहतर बनाने के लिए व इनकी पृष्ठ संख्या बढ़ाने के लिए पाठकों की ओर से आए सुझाओं की चर्चा की उन्होंने इस संबंध में सीटू केंद्र द्वारा झेली जा रही दिक्कतों के बारे में बताया. उन्होंने मद्रास कांफ्रेंस के बाद के समय में सीटू केंद्र द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा अन्य प्रकार की प्रकाशन सामग्री का ब्योरा भी दिया.

सीटू केंद्र के कार्यक्षेत्र में विस्तार तथा काम में बढ़ोतरी होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि सीटू केंद्र को मजबूत बनाया जाए तथा अधिक साथी इसमें स्थायी रूप से काम करें.

अपनी रिपोर्ट का समापन करते हुए सीटू सचिव एम. के. पंधे ने बताया कि सीटू को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को एक मंच पर लाने के लिए पहलकदमी करनी होगी जिससे कि तमाम ट्रेड यूनियन आंदोलन मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एकजुट हो लड़ सके.

सीटू का नवीनतम प्रकाशन

खदानों में कामगार महिलाओं की दशा

कीमत : 70 पैसे

मिलने का पता :

सी. आई. टी. यू. कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड़,
नई दिल्ली-110001

[पृष्ठ सात से आगे]

के लोगों को आपस में लड़ाने की नीति के फलस्वरूप शीतयुद्ध भारत के दरवाजे तक आ गया है. मजदूर वर्ग को साम्राज्यवादियों के इन नापाक मंसूबों के खिलाफ देश की जनवादी ताकतों को सचेत करना है तथा देश की एकता, शांति व आजादी की रक्षा के लिए आम जनता को तैयार करना है. अफसोस की बात है कि देश की राजनीतिक शक्तियों का एक भाग अपने तात्कालिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए राष्ट्रविरोधी तत्वों की ओर से आने वाले खतरों के प्रति आंखे मूंद रहा हैं. एन प्रसाद राव प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं.

कीमत वृद्धि पर

पी. सुंदरय्या बढ़ते मूल्यों पर प्रस्ताव रखते हैं. इसमें आम जरूरत की चीजों को सार्वजनिक रूप से संग्रहित व वितरित करने के लिए लगातार आंदोलन चलाए जाने, किसानों को उत्पादन की सही कीमत देने तथा कालेबाजारियों व जमाखोरों को सख्त सजा देने की जरूरत पर बल दिया गया है. प्रस्ताव में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व किसान संगठनों को संयुक्त संघर्ष के लिए एक विस्तृत मंच पर आने व मूल्य वृद्धि, जरूरत की चीजों की उपलब्धि, उपज की सही कीमत आदि मसलों पर संयुक्त संघर्ष चलाने की अपील की गई है. सुंदरय्या ने मजदूर वर्ग से कहा कि किसानों की समस्याओं पर वे अपना समर्थन दें तथा इन पर एक लंबा संयुक्त संघर्ष छेड़ने के लिए तैयार रहें. मुहम्मद इस्माइल ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया.

पी. आर. कृष्णन ने कम्प्यूटराइजेशन के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया इसमें सभी ट्रेड यूनियन केन्द्रों से अपील की गई है कि वे आटोमेशन व बेरोजगारी के खिलाफ तथा नौकरी की संभावनाएं बनवाने के लिए संयुक्त रूप से आवाज उठाए. एन. नंजुनदप्पा ने इसका अनुमोदन किया.

इस बीच कई और प्रस्ताव भी पारित हो गए हैं—इनमें मुख्य है शांति की रक्षा व जंगबाजों के खिलाफ प्रस्ताव, सीमावर्ती सड़क संस्थान के कर्मचारियों पर हो रहे अभूतपूर्व दमन के खिलाफ प्रस्ताव, केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर प्रस्ताव, जूट कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रस्ताव तथा सांप्रदायिक झगड़ों पर प्रस्ताव. प्रस्ताव समिति को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वह अन्य मुद्दों पर स्वयं ही प्रस्तावों को अंतिम रूप दे.

पी. राममूर्ति तीन सदस्यों को जनरल काउंसिल का सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव रखते हैं. ये सदस्य हैं--मैथली शिवरमण (तमिल नाडु), विजेंद्र शर्मा (सीटू केंद्र) व टी. एन. नबीराजन (सीटू केंद्र). ये सर्वसम्मति से शामिल कर लिए जाते हैं.

पी. राममूर्ति प्रमोशन में आरक्षण की नीति का मुद्दा बहस के लिए प्रस्तुत करते हैं. बहस में 11 सदस्य भाग लेते हैं—पी. सुंदरय्या, जीवेन राय, शांति घटक, एन. प्रसाद राव, के. एम. हरी भट्ट, तरित तोपदार, विश्वनाथ मेनन, पी. दक्षी, के. के. राय गांगुली, अबुल हसन तथा एस. एस. भट्टाचार्य. राममूर्ति इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करने के लिए सदस्यों से सुझाव व उदाहरण मांगते हैं जो कि लिखित रूप में एक महीने के भीतर सीटू केंद्र को मिल जाने चाहिए. इसके बाद ही इस पर अन्तिम फैसला लिया जाएगा.

ए. नल्लसिवन ने क्रीडेंशल कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस कमेटी को 181 यूनियनों के प्रार्थनापत्र मिले हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 28 हजार है.

14 सितंबर : जनरल काउंसिल के सदस्य कन्नानोर से 18 किलोमीटर दूर ए. के. गोपालन मेमोरियल को देखने जाते हैं. सदस्य दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इस स्थान पर 3000 से अधिक व्यक्तियों की एक सभा में अन्य नेताओं के अतिरिक्त समर मुखर्जी भाषण देते हैं. सारा रास्ता लाल झंडों से सजा है.

जन संघर्षों की अगुवाई

पी. राममूर्ति समापन भाषण करते हैं. वे कहते हैं कि एकता व एकजुट संघर्ष का जो परिचय सीटू के स्थापना सम्मेलन में बुलंद किया गया था, आज वह फल दे रहा है. तब से अब तक के सभी मजदूर संघर्षों में सीटू ने अहम भूमिका निभाई है. वे कहते हैं कि इस बैठक में हमने मजदूर वर्ग व देश की समस्याओं पर विचार विमर्श किया है. हम केवल आर्थिक मांगों के आधार पर ही आगे नहीं बढ़ सकते. केवल आर्थिक मुद्दों पर उठाए गए संघर्ष ही समाज का ढांचा नहीं बदल सकते. मजदूर वर्ग को सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक, विचारधारात्मक व वर्ग आधार पर भी लड़ना होगा. हमें मजदूर वर्ग की एकता के लिए भी संघर्ष करना होगा और यह एकता ही नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का काम करेगी. यदि मजदूर वर्ग इन समस्याओं की चुनौती का सामना के लिए तैयार नहीं होता तो आम जनता की मुसीबतें दिन-दिन बढ़ती जाएंगी. मजदूर वर्ग तथा सीटू को जनता के संघर्षों का अगुवा बनना होगा और शांति, जनवाद का झंडा ऊंचा उठाना होगा. धन्यवाद प्रस्ताव के बाद बैठक समाप्त होती है.

यहां यह बताना आवश्यक है कि 10 व 15 सितंबर को पूरे दिन तथा अन्य दिनों भोजन अवकाश के समय उद्योग स्तर की बैठकें हुईं जिनमें इन उद्योगों के भीतर तालमेल की जरूरत पर ध्यान दिया गया. इनमें प्रमुख उद्योग हैं—सड़क परिवहन, गोदी व बंदरगाह, प्लांटेशन, कोयला, इंजीनियरिंग, तथा बिजली. 14 सितंबर को हिंदी क्षेत्र के जनरल काउंसिल सदस्यों की एक बैठक हुई जिसमें सीटू के प्रकाशनों पर बातचीत हुई. स्वागत समिति ने 11, 12 व 13 सितंबर की रातों में सांस्कृतिक

[शेष पृष्ठ चौदह पर]

जनरल काउंसिल...

[पृष्ठ तेरह से आगे]

कार्यक्रमों का आयोजन किया था. इन कार्यक्रमों से सदस्यों को केरल की संस्कृति की एक झलक मिली. 'लेनिन इनअ क्तूबर' नामक एक फिल्म भी दिखायी गयी.

अपराह्न 4 बजे मिलीट्री ग्राउंड से सीटू नेताओं व जनरल काउंसिल सदस्यों के नेतृत्व में एक जुलूस निकलता है. रास्ते में सड़कों के दोनों ओर खड़े हजारों लोग जुलूस का अभिनंदन करते हैं. सारा रास्ता लाल रंग की झंडियों से सजा है. ट्रेड यूनियनों व एसोसियेशन ने स्वागत द्वार सजाए हैं. गगनभेदी नारों से वातावरण गूंज रहा है. जुलूस का अभिनंदन करनेवालों में फैक्ट्री व खेत मजदूर, बीमा, रेलवे, बैंक, डाक व तार के कर्मचारी, छात्र, युवक, स्कूल व कालेज के अध्यापक व असंख्य जनता है. चारों ओर 'लाल सलाम' की आवाजें गूंज रही हैं. महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जुलूस के साथ हैं. जुलूस स्टेडियम ग्राउंड पहुंच गया है. 50 हजार से अधिक लोगों की आम सभा में जुलूस समाप्त होता है. आम सभा की अध्यक्षता सुशीला गोपालन कर रही है. सीटू के शीर्षस्थ नेता हर्षध्वनि के बीच जनरल काउंसिल में लिए फैसलों को सुना रहे हैं. ये हैं : सी. कन्नन, सुशीला गोपालन, पी. राममूर्ति, समर मुखर्जी, पी. सुंदरय्या, एम. के. पंधे और ई. बालानंदन

पी. राममूर्ति...

[पृष्ठ नौ से आगे]

धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है. उन्होंने कहा कि एक समय तो इंदिरा गांधी ने स्वयं भी 'भूमिपुत्र' के नारे को समर्थन दिया था. आज भी उनके कई मुख्यमंत्री इस सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं. उन्होंने ट्रेड यूनियन आंदोलन का आह्वान किया कि वह पृथकतावादी शक्तियों व साम्राज्यवादियों द्वारा देश को छिन्न-भिन्न करने के षड़यंत्रों का डटकर मुकाबला करें. मजदूर वर्ग व संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन को देश की आजादी व एकता के लिए किए जा रहे आंदोलन का अगुवा बनना होगा.

साम्राज्यवादी जंगबाजों के खिलाफ संघर्ष आज के हालात में विशेष महत्व रखता है. यह संघर्ष आजादी व एकता को बनाए रखने व देश पर नवउपनिवेशवाद थोपने के षड़यंत्र को हराने के लिए आवश्यक है. सीटू महासचिव ने अन्त में कहा: "इस संघर्ष में हम किस सीमा तक मजदूर वर्ग को गोलबंद कर पाएंगे, यह सर्वहारा के अंतर्राष्ट्रीयतावाद की परीक्षा होगी."

फरीदाबाद सीटू का सम्मेलन

सीटू की फरीदाबाद जिला समिति ने 25 अगस्त को एक दिन का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लगभग 475 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सम्मेलन की अध्यक्षता फरीदाबाद सीटू के अध्यक्ष दीवन गांधी ने की. सम्मेलन में सीटू की दिल्ली राज्य समिति के अध्यक्ष चाचा शादीराम, व सचिव जोगेंद्र शर्मा तथा फरीदाबाद सीटू के महासचिव मोहनलाल ने भी भाषण दिये.

सम्मेलन में पास किए गए प्रमुख प्रस्ताव हैं—फरीदाबाद के विभिन्न उद्योगों में छंटनी किए गए 10 हजार से अधिक मजदूरों की बहाली, 17 अक्टूबर को हुए पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जांच तथा मृतकों के परिवारों को समुचित मुआवजा, यूनियन नेताओं के खिलाफ दायर किए गए झूठे केसों को वापिस लेना, खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन देना, किसानों को फसलों का सही दाम देना तथा बेरोजगारों को काम न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देना.

सम्मेलन ने अपने 13-सूत्री कार्यक्रम को लागू करवाने के लिए आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया तथा फरीदाबाद की तमाम मेहनतकश जनता को आह्वान किया कि वे इस संघर्ष में पूरी तरह से जुट जाएं.

बी. टी. रणदिवे...

[पृष्ठ चार से आगे]

की. किंतु इस प्रकार के सभी नापाक प्रयत्न असफल हो गए हैं. वामपंथी मोर्चा सरकार आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने में सफल रही हैं. इसने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रतिक्रियावादी तत्वों को हराने का एक ही हथियार है और वह है आम आदमी को न्याय देना, उसको राहत पहुंचना" उन्होंने मजदूर वर्ग का आह्वान किया कि वह सहायता शिविरों में अधिक से अधिक आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाएं. इसके साथ-साथ वह त्रिपुरा सरकार के लिए मजदूर वर्ग की राजनीतिक सहानुभूति अर्जित करें.

सीटू अध्यक्ष ने बताया कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को पूरे जोर से आम जनता पर पड़ रहे मूल्य वृद्धि के भार के खिलाफ संघर्ष में हिस्सा लेना चाहिए था किंतु वह अब तक इस बारे में अधिक नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा: "हमें फौरी मुद्दों व समस्याओं पर आंदोलन छेड़ने के लिए तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, फेडरेशनों व अन्य संस्थाओं को एक समान मंच पर लाना होगा." मजदूर वर्ग की इस प्रकार की एकजुट शक्ति आम जनता व राष्ट्रहितों से संबंधित नीतियों पर प्रभाव डाल सकती है. संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि वह किसानों व खेतिहर मजदूरों की समस्याओं को उठाएं क्योंकि ये वर्ग कमजोर संगठन होने के कारण भारतीय जनता में सबसे अधिक शोषित है.

भाषण का समापन करते हुए सीटू अध्यक्ष ने कहा: "ट्रेड यूनियन आंदोलन इस देश की वामपंथी व जनवादी ताकतों की शक्ति का मुख्य श्रोत व आधार बन सकता है. यदि हम एकजुट हो जाएं तो वामपंथी व जनवादी ताकतें सुदृढ़ होंगी. प्रतिवादी हिंदू सांप्रदायिकता से संघर्ष करते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाना है व अधिनायकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए विस्तृत मंच तैयार करने के लिए वामपंथी ताकतों को मजबूत करना है."

तीसरी रेलवे फेडरेशन बनाने का कोई विचार नहीं

सीटू महासचिव व संसद सदस्य पी. राममूर्ति ने 31 अगस्त को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

हमारा ध्यान कुछ अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि सीटू रेलवे मजदूरों की एक तीसरी फेडरेशन के गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है. सीटू का यह विचार है कि रेलवे मजदूर आंदोलन पहले से ही बिखरा हुआ है तथा चार फेडरेशनों व एक कनफेडरेशन के अलावा कई कैटेगरीवाइज यूनियनें, एसोसियेशनें व स्थानीय औद्योगिक यूनियनें इसमें काम कर रही हैं. सीटू हमेशा से रेलवे मजदूर आंदोलन में एकता का हिमायती रहा है. 1974 की रेलवे हड़ताल में भी सीटू ने एकता की जरूरत पर जोर दिया था.

सच्चाई यह है कि आंदोलन के इस बिखराव को दूर करने के लिए कुछ कैटेगरीवाइज एसोसियेशनें व यूनियनें एक समन्वय समिति बनाने का प्रयत्न कर रही है. इस समिति का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों की फौरी समस्याओं पर एकजुट आंदोलन चलाना है. सीटू द्वारा एकता के इन प्रयत्नों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि सीटू तीसरी फेडरेशन का गठन कर रही है बेबुनियाद व शरारतपूर्ण प्रचार है. इसका उद्देश्य रेलवे मजदूरों में एकता की बढ़ती हुई भावना को रोकना व आंदोलन को विभाजित करना है.

सीटू को पूरी आशा है कि रेलवे मजदूर इस प्रकार के द्वेषपूर्ण प्रचार से गुमराह नहीं होंगे और तमाम रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष में एकता बनाने के अपने प्रयत्न जारी रखेंगे.

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की सीटू द्वारा निंदा

सीटू के सचिव एम के पंधे ने 23 सितंबर को जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि सीटू राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की कड़ी निंदा करती है. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक नजरबंद रखा जा सकता है. यह कदम और कुछ न होकर नये आवरण में मीसा की पुनरावृत्ति है. हालांकि इसमें सांप्रदायिकता, पृथकतावाद आदि से निबटने की बात कही गयी है, लेकिन इसका असल मकसद है देश के ट्रेड यूनियन और जनवादी आंदोलन को कुचलना.

गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा जारी ऐसे ही आदेशों के बाद घोषित इस अध्यादेश का मकसद है लोगों को बदले की भावना से नजरबंद करने और सरकार के खिलाफ प्रत्येक कार्रवाई को कुचलने के लिए प्रशासन को मनमाने अधिकार देना. इसका इस्तेमाल मालिकान के हितों की रक्षा के लिए मजदूरवर्ग के आंदोलनों और हड़तालों के खिलाफ किया जायगा.

सलाहकार बोर्ड का प्रावधान आंखों में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है क्योंकि इससे हालात में कोई फर्क नहीं आनेवाला. लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मीसा के दौरान सरकार ने पुनरीक्षण के प्रावधान का कितना दुरुपयोग किया था.

नजरबंदी को चुनौती देते हुए कोर्ट में अपील कर सकने के अधिकार से भी कुछ नहीं होगा. क्योंकि आंदोलन और हड़ताल के नाजुक मौकों पर कानूनी प्रक्रिया के कारण नजरबंदी का ही उद्देश्य पूरा होगा.

सीटू तमाम ट्रेड यूनियनों से अपील करती है कि वे सारी ताकत जुटाकर संयुक्त रूप से इस काले अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष करें जिससे कि केंद्रीय सरकार को इस तानाशाहीपूर्ण कदम को वापस लेने पर मजबूर किया जा सके.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980 मई	जून	जुला.
बिहार			
जमशेदपुर	375	378	386
झारिया	356	360	368
कोडर्मा	399	410	412
मोंघाइर	406	410	422
नोआमुंडी	368	376	377
गुजरात			
अहमदाबाद	365	366	371
भाव नगर	395	391	399
हरियाणा			
यमुना नगर	418	423	436
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	396	404	409
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	405	406	419
भोपाल	377	385	393
ग्वालियर	408	415	425
इंदौर	393	396	409
महाराष्ट्र			
बंबई	385	389	399
नागपुर	377	382	392
शोलापुर	384	389	401
पंजाब			
अमृतसर	388	394	408
राजस्थान			
अजमेर	401	405	420
जयपुर	411	425	433
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	381	381	389
सहारनपुर	388	394	401
वाराणसी	438	442	446
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	390	391	395
कलकत्ता	371	375	381
दार्जीलिंग	321	325	327
हावड़ा	353	359	363
जलपाइगुरी	323	323	331
रानीगंज	380	375	379
दिल्ली	407	412	423
भारत	382	386	394

सरकार द्वारा रथ कमेटी रिपोर्ट अस्वीकार : सीटू का विरोध

सीटू सचिव एम. के. पंधे ने सरकार द्वारा रथ कमेटी रिपोर्ट को नामंजूर किए जाने के फैसले की निंदा करते हुए केंद्रीय श्रममंत्री टी. अंजैया को एक सितंबर को निम्न पत्र भेजा है :

"हमें यह जानकर हैरानी हुई है कि भारत सरकार ने कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स नंबर्स रिव्यू कमेटी (रथ कमेटी) की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है. हालांकि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1978 के आरंभ में दाखिल कर दी थी किंतु सरकार ने इस पर फैसला लेने में इतना अधिक समय लगाया.

जैसा कि आप जानते ही हैं, इस कमेटी में सीटू के प्रतिनिधियों ने इस रिपोर्ट से लिखित रूप में अपनी असहमति प्रकट कर दी थी क्योंकि उनके विचार में इसकी सिफारिशें सूचकांक की असंगतियों को पूरी तरह ठीक नहीं करती थी. हमारा अब भी यही विचार है यह सूचकांक बढ़ती हुई महंगाई व मजदूर वर्ग पर बढ़ते हुए मूल्यों के भार को सही प्रकार से दर्शाने में असमर्थ है. किंतु सरकार के इस फैसले ने उस कमेटी द्वारा उपभोक्ता सूचकांक में समझाए गए सीमित परिवर्तनों पर भी पानी फेर दिया है. सरकार का यह फैसला सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के उन मालिकान को खुश करने के लिए किया गया है जो सदा से ही शोर मचाते आ रहे हैं कि 1960 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है. केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विशेषकर वित्त मंत्रालय, 1960 के अंकों में परिवर्तन लाने के किसी भी प्रयत्न का विरोध करते आ रहे हैं. सरकार का यह निर्णय यह दर्शाता है कि बड़े औद्योगिक घराने किस प्रकार सरकार पर हावी हैं.

हमें पता चला है कि लेबर ब्यूरो ने 1960 के अंकों में परिवर्तन किये बिना ही 1980 के लिए परिवार बजट अध्ययन आरंभ कर दिया है. हमारे विचार में 1960 के सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता न दिया जाए, तब तक परिवार बजट अध्ययन भी मजदूरों के परिवार में खपत का गलत उदाहरण पेश करेगा.

इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि सरकार ने इस मुद्दे पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन की एक बैठक बुलाकर कोई सर्वसम्मत आधार बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया. इसके स्थान पर सरकार ने ट्रेड यूनियनों की यूनिट स्तर की बैठकें बुलवाकर उनसे परिवार बजट अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र करने पर विचार किया. सरकार की यह पद्धति अनियमित है और इससे मजदूरों का सूचकांक निर्धारण मशीनरी से विश्वास ही उठ जायेगा.

रथ कमेटी ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एक स्टैंडिंग एडवाइजेरी कमेटी के गठन की सिफारिश की हैं जिसमें ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है. किंतु इस प्रकार की किसी कमेटी का गठन नहीं किया गया.

सीटू सरकार द्वारा रथ कमेटी की सिफारिशों को नामंजूर किये जाने व ऐसे हालात में लेबर ब्यूरो द्वारा 1980 के लिए परिवार बजट अध्ययन के काम को शुरू करने के खिलाफ अपना सख्त विरोध प्रकट करती है.

सीटू यह मांग करती है कि इस मुद्दे पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की एक बैठक तत्काल बुलाई जाए जो इस पूरे सवाल पर विचार करे व सूचकांक को ठीक करे अन्यथा बढ़ती महंगाई के दौर में यदि सूचकांक के निर्धारण पद्धति से मजदूरों का विश्वास हट जाएगा तो गंभीर औद्योगिक अशांति फैल सकती है.

मुझे विश्वास है कि आप हालात की गंभीरता को समझेंगे व शीघ्र ही केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक बुलाएंगे."

कीमत वृद्धि, सांप्रदायिकता के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन

छः पार्टियों—सी. पी. आई. (एम.), सी. पी. आई., लोकदल, कांग्रेस (अर्स), फारवर्ड ब्लाक व आर. एस. पी.—कोआर्डिनेशन कमेटी नई दिल्ली में 27 व 28 सितंबर को बढ़ती कीमतों, खतरनाक सांप्रदायिक व अधिनायकवादी विचारधाराओं, तथा जनता के जनवादी अधिकारों पर हमलों के खिलाफ दो-दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करेगी.

सीटू मजदूर

के 1979 के सभी अंक अब जिल्द के रूप में उपलब्ध हैं.

कीमत : दस रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति   मनोरंजन राय
नीरेन घोष   सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 97-98, डीएसआईडीसी कम्पलैक्स, ओखला, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित